It is said that there are clear efforts to divide the people on communal lines and to terrorise the Muslims engaged in tailoring and other vocations. Anti-Muslim and Anti-Christian slogans are also plastered across some walls in the town. Yet the State Government officials plead ignorance about the goings on in Kotdwar in Uttaranchal. The Uttaranchal Lady Tailors' Association has met the Police Commissioner to complain about the harrassment. Sir, I bring these incidents to your notice so that you may direct the Government to curb such incidents indulged in by the fundamentalists and not to allow Indian society to be divided on communal lines. It looks like, some vested interests, for the sake of political gains, are creating communal tension. This is absolutely against the secular fabric of the Indian society. It should be curbed at once. Let not men use women as tools to divide the society and rule. It is indeed shameful and needs to be condemned so that it doesn't spread its tentacles all over the country.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA (Andhra Pradesh): Sir, I associate myself with this Special Mention.

Need for procurement of Copra by NAFED

SHRI V.V. RAGHAVAN (Kerala): Sir, the Minimum Support Price for Copra was declared by the Government of India for the year 2001 at Rs.3,300 and Rs.3,500 per quintal for different varieties. But the market price has crashed to Rs. 1,900 per quintal. The price crash is basically due to the import of palmolein at reduced import duty. Despite repeated promises by the Minister of Agriculture and the Prime Minister, NAFED has not procrred Copra from Kerala till now. Thirty lakh coconut cultivators of Kerala are driven to mass suicide because of this price crash and debt burden. Hence, I urge upon the Government to direct NAFED to start procurement of Copra without further delay.

Problem of Hand-Pulled Rickshaw Pullers of Howrah and Kolkata

श्री श्याम लाल(उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान पश्चिमी बंगाल के हावड़ा और कोलकाता नगर में हाथ से रिक्शा खींचने वालों की मुख्य समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर , आज विश्व का मानव समाज वैज्ञानिक प्रगति की सभ्यता के वातावरण में जीवनयापन कर रहा है। यातायात व आवागमन के नए-नए साधनों का प्रयोग किया जा रहा है । घोड़ों से तांगा खींचने का स्थान कार व मोटर गाड़ीयों ने ले लिया है और खच्चरों से सामान की दुलाई का स्थान ट्रक व अन्य वाहनों ने ले लिया है, परन्तु पश्चिमी बंगाल के हावड़ा व कोलकाता महानगरियों में आज मनुष्य घोड़ों व खच्चरों की भांति सीने के बल हस्तचालित रिक्शा खींच रहा

है। ऐसे रिक्शे के मालिक सैकड़ों रिक्शों किराए पर चलवाते हैं। इस तरह ऐसे हाथ से रिक्शा चलाने वाले का स्वास्थ्य समय से पूर्व अस्वस्थ हो जाया करता है और वे असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाया करते हैं।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि हाथ से सीने के बल रिक्शा खीचने वाली अमानवीय तथा कलंकित करने वाली व्यवस्था समाप्त की जाए और ऐसे रिक्शा चालकों के वैकल्पिक जीविकोपार्जन हेतु व्यवस्था करने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को निर्देशित किया जाए । ऐसे रिक्शों के स्थान पर मोटरेबल रिक्शों चलवाए जाएं मुफ्त मेडिकल व्यवस्था तथा आश्रयगृह बनवाए जाएं। 12 से ज्यादा रिक्शा रखने वाले मालिकों को कम्पनी एक्ट के अधीन पंजीकृत करवाया जाए और रिक्शा चालकों की आठ घंटे की पारी सुनिश्चित कराई जाए तथा उनके लिए एल.आई.सी. की व्यवस्था भी की जाए। धन्यवाद।

Irregularities in purchase of Paddy

श्री जनेश्वर मिश्र(उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मेरा स्पेशल मेंशन धान की खरीदारी में की जा रही धांधली के संबंध में है। अभी हम लोग नारियाल और कपास के बारे में सुन चुकें हैं।

महोदय, आज देश में धान पैदा करने वाला किसान विचित्र तबाही के दौर से गुजर रहा है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 515 रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो किसानों की कुल लागत एवम् मेहनतानें के हिसाब से बहुत कम है। ये बातें सरकार और समर्थन मूल्य तय करने वाले भी जानते हैं, परन्तु किसानों की पैदावार धान की बिक्री का कोई समुचित प्रबंध नहीं है। सरकारी क्रय केन्द्रों पर तरह तरह कि अड़ंगेबाजियां लगाई जाती हैं और उनका धान क्रय-केन्द्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है तथा उनका बराबर शोषण किया जा रहा है सरकार बोल रही है कि उसके पास चावल का इतना भंड़ारण है कि उसको रखने की उसके रखने की उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है जिसके चलते किसान अपनी धान कि पैदावार को बाजार के दलालों-बिचौलियों के हाथों जगह नहीं है जिसके चलते पास चावल किसन अपनी धान कि पैदावार को बाजार के दलालों-बिचौलियों के हाथों 300-350 रूपए प्रति क्विंटल बेचने पर मजबूर है। देश कि यह प्रमुख पैदावार है इसलिए पैदा होने के बाद इसकी यह दशा होना मेरी समझ से परे है। सरकार जानकर भी कुछ नहीं कर पा रही है जिसका खामियाजा देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बिचौलियों एवम् क्रय केन्द्रों के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते किसानों से औने-पौने दामों में खरीदा गया धान क्रय-केन्द्रों पर सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा जा रहा है, जिसके चलते किसानों के बेचने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती।

मैं सरकार के कृषि के एवम् खाद्य मंत्रालय से मांग व गुजारिश करूंगा कि कृपया वे देश के किसानों को बचा लें नहीं तो वे बर्बाद हो जाएंगे और यह भी मांग करूंगा कि इस संबंध में सरकार सदन में एक वक्तव्य दे और इसके लिए कारगर कदम उठाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

I

SHRI EDUARDO FALEIRO (GOA) : Sir, I associate myself.